

शासन में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता

सूचना क्या है?

- सूचना वह डेटा है जिसे व्यवस्थित या वर्गीकृत किया गया है और प्राप्तकर्ता के लिये इसका कोई विशेष महत्त्व है। सूचना संसाधित डेटा है जिस पर नषिकर्ष और प्रतिक्रियाएँ आधारित होती हैं।
- नरिणय लेने में सूचना महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिलती है। नरिणय लेने का महत्त्व सूचना की सटीकता, पूरुणता और समय पर नरिभर करता है।
- डेटा एक नया तेल है और डेटा प्रोसेसिंग द्वारा सूचना का अनुकरण किया जाता है।

सूचना साझाकरण क्या है?

- सूचना साझाकरण एक इकाई द्वारा नरिंत्रित अन्य लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने का स्वैच्छिक कार्य है।
- कई कंपनरियों, व्यक्तियों और प्रौद्योगिकी के बीच डेटा का आदान-प्रदान सूचना साझाकरण के रूप में जाना जाता है।
- व्यापक वतितरि नेटवर्क, इंटरनेट, क्रॉस-प्लेटफॉर्म संगतता, एप्लिकेशन पोर्टिंग और आईपी प्रोटोकॉल मानकीकरण ने वैश्विक सूचना आदान-प्रदान में जबरदस्त वृद्धि को सक्षम किया है।

सूचना साझा करने में नैतिकता को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता कैसे बनाए रखा जा सकता है?

- पारदर्शिता में जानकारी का खुलासा करना और खुले और ईमानदार तरीके से संचालन करना शामिल है।
- पारदर्शिता प्राप्त करने के लिये सूचना की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- सूचना साझा करने की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सूचना की प्रसंगिकता, पारदर्शिता, सटीकता और समय पर नरिभर करती है।
- सूचना साझा करने में पारदर्शिता सरकार की तरफ से जवाबदेही और जमिमेदारी का आश्वासन देती है।
- पारदर्शिता बनाए रखने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार एक मूलभूत आवश्यकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

- सूचना के अधिकार (RTI) ने तब शक्ति प्राप्त की जब वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिसमें सभी को कसि भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किये बिना प्राप्त करने, सूचना और वचिरों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- **अधिनियम के उद्देश्य:**
 - नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये
 - पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये
 - भ्रष्टाचार को रोकने के लिये
 - लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
- **सूचना अधिनियम को अपनाने के कारण:**
 - सूचना अधिनियम को अपनाने के लिये जमिमेदार कारक इस प्रकार हैं:
 - भ्रष्टाचार और घोटाले
 - अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सकरयिता
 - आधुनिकीकरण और सूचना समाज

महत्त्व:

- **आरटीआई अधिनियम, 2005** ने कानून को लागू करने के लिये एक नई नौकरशाही का नरिमाण नहीं किया। इसके बजाय इसने प्रत्येक कार्यालय में अधिकारियों को अपने स्वैये और कर्तव्य को गोपनीयता के स्थान पर सार्वजनिक रूप से साझा करने और खुलेपन में बदलने का काम सौंपा और अनवार्य किया।
- इसने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रदान करने हेतु देश के कसि भी कार्यालय को आदेश देने के लिये सूचना आयोग को सावधानीपूर्वक और जानबूझकर देश में सर्वोच्च प्राधिकारी होने का अधिकार दिया। साथ ही, इसने आयोग को जनादेश का पालन नहीं करने वाले कसि भी अधिकारी

पर जुरमाना लगाने का अधिकार दिया।

- सूचना के अधिकार को सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने और जन केंद्रित शासन की शुरुआत करने की कुंजी के रूप में देखा गया है।
- सूचना तक पहुंच समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिये सशक्त बना सकती है, जिससे उनका कल्याण हो सके।
- अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नरिणय लेने में सुधार करता है।

ई-खरीद

■ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल:

- राष्ट्रीय सूचना वजिज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खरीद नीति प्रभाग, वित्त मंत्रालय के साथ मलिकर केंद्र सरकार के वभिाग और अन्य संगठनों के लिये इलेक्ट्रॉनिक खरीद / नविदि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनुकूलति केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल विकसति और कार्यान्वति कयिा है।
- पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य वभिनिन् मंत्रालयों और संबंधति वभिागों में की गई खरीद के बारे में जानकारी के लिये एकल बदि पहुंच प्रदान करना है।
- ऑनलाइन खरीद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (GeM) के माध्यम से की जाती है
- **GeM वभिनिन् केंद्रीय और राज्य सरकार के वभिागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये एक स्थान पर राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।**
- यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रविर्स ई-नीलामी के उपकरण भी प्रदान करता है।

■ वजिन

- एक पारदर्शी, कुशल और समावेशी बाजार को विकसति करने के लिये सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देना।

■ मशिन:

- व्यवहार परविरतन को प्रोत्साहित करने के लिये एक एकीकृत खरीद नीति स्थापति करना।
- नरितर नवाचार और बाजार द्वारा संचालति नरिणय लेने में सक्षम एक गतशील संगठन स्थापति करना।
- खरीद में पारदर्शति और दक्षता सुनश्चिति करने के लिये उपयोग में आसान, पूरी तरह से स्वचालति प्लेटफॉर्म का नरिमाण करना।
- सही कीमत पर सही गुणवत्ता सुनश्चिति करके मूल्य प्रदान करने की प्रतबिद्धता प्रदर्शति करें।
- सभी हतिधारकों को शामिल करते हुए और भारत में समावेशी विकास को चलाने के लिये एक स्थायी पारस्थितिकी तंत्र बनाएँ।

■ सदिधांत:

- प्रतबिद्धता
- जवाबदेही
- स्वामतिव और जवाबदेही
- पारदर्शति और अखंडता
- सामाजिक समावेशन
- प्रक्रयिा सरल बनाने के लिये नवाचार

■ ई-शासन:

- ई-गवर्नेंस को सरकारी सेवाएँ प्रदान करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, लेनदेन, पहले से मौजूद सेवाओं और सूचना पोर्टलों के एकीकरण के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषति कयिा जा सकता है।

■ ई-गवर्नेंस चुनने के कारण:

- शासन व्यवस्था बहुत जटलि हो गई है।
- सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि।

■ उद्देश्य:

- नागरिकों को बेहतर वतिरण सेवा।
- पारदर्शति और जवाबदेही की शुरुआत।
- जानकारी के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।
- सरकार के भीतर यानी केंद्र-राज्य या अंतर-राज्यों के बीच दक्षता में सुधार।
- व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार।

■ ई-गवर्नेंस के सतंभ:

- जनता
- प्रक्रयिा
- तकनीक
- साधन

■ ई-गवर्नेंस में अंतःक्रयिा के प्रकार

- G2G यानी, सरकार से सरकार
- G2C यानी, सरकार से नागरिक
- G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस
- G2E यानी सरकार से कर्मचारयिों तक

पारदर्शति और सूचना साझाकरण का महत्त्व

- पारदर्शिता बनाए रखने और सूचना साझा करने का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू संचार बाधाओं को दूर करना है।
- जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये पारदर्शिता और सूचना साझा करना महत्त्वपूर्ण है।
- सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन में नागरिकों का समर्थन और भागीदारी खुलेपन और जवाबदेही को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- प्रभावी प्रशासन और शासन की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिये सूचना साझा करने में पारदर्शिता आवश्यक है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

Q. हाल के दिनों में, भारत में प्रभावी सविलि सेवा नैतिकता, आचार संहिता, पारदर्शिता उपायों, नैतिकता और अखंडता प्रणाली और भ्रष्टाचार वसिधी एजेंसियों को वकिसति करने की चति बढ रही है। इसे देखते हुए,

1. सविलि सेवाओं में नैतिक मानकों और अखंडता के लिये वशिष प्रकार के खतरों की आशंका,
2. सविलि सेवक की नैतिक क्षमता को मजबूत करना और
3. प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं का वकिस करना जो सविलि सेवाओं में नैतिक मूल्यों और अखंडता को बढावा देते हैं।

उपर्युक्त तीन मुद्दों के समाधान के लिये संस्थागत उपायों का सुझाव दें।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/information-sharing-and-transparency-in-government>

